भारत की सुरक्षा चिन्तादंड : नेपाल के परिप्रेक्ष्य में

मित्तलबेन एम. वाघेला
एम.ए., बी.एड,एम.फील, पीएच.डी (स्कोलर)
नडियाद

ABSTRACT

नेपाल, भारत का सामरिक रुप से महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है । दोनों देशों के मध्य सदियों से चले आ रहे ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक व आर्थिक सम्बन्ध विश्व में अपने आप में विशिष्ट है जो अन्यत्र कहीं और देखने को नहीं मिलता है । भारत और नेपाल के मध्य रिश्ते सामान्य होने पर कोई विवाद नहीं होता परन्तु जैसे ही नेपाल में राजनैतिक उतार-चढाव होता है, तो नई दिल्ली तथा काठमाण्डू के बीच पुराने विवाद विस्फोटक संकट का रुप ग्रहण कर लेते है । इन्हीं परिस्थितियों का लाभ उठाकर भारत विरोधी शक्तियाँ यथा-चीन तथा पाकिस्तान वहाँ सक्रिय होकर भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न करने लगते हैं । प्रस्तुत लेख में नेपाल की तरफ से भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले कारकों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है ।

प्रस्तावना :

नेपाल की पहचान संसार में एकमात्र हिन्दू राज्य के रुप में की जाती है । यह एक स्थरुद्ध देश है । भारत और चीन दो एशियाई दिग्गज देशों के साथ इसकी सीमाएँ मिलती है । तीन तरफ पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण में भारत से तथा उत्तर में चीन के मध्य एक बफर राज्य माना जाता है । भारत के ५ राज्य सिक्किम, पं. बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड नेपाल के साथ १७५१ कि.मी. लम्बी सीमा बनाते है ।

विश्व में भारत-नेपाल जैसा अद्वितीय सम्बन्ध अन्यत्र कहीं और देखने को नहीं मिलता है । सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर दोनों देशों में इतनी अधिक समानता है कि दोनों के बीच राजनैतिक विभाजन कठिन हो जाता है । इसलिए कहा जाता है कि भारत-नेपाल सम्बन्ध अपने किसी महत्व से ज्यादा भूगोल व इतिहास से निर्धारित होता है । इन्हीं सम्बन्धों की विशिष्टता को इंगित करते हुए पुष्पेश पंत कहते है कि ''सीमावर्ती इलाके में रहने वाले भारतीय और नेपाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को बाधा या रुकावट के रुप में नहीं देखतेत, न केवल यहाँ के गाँवों-कस्बों के निवासियों के बीच रोटी-बेटी का सम्बन्ध है सढ़ियों से बल्कि आर्थिक जीवन के ताने-बाने भी आपस में गुंथे हुए हैं ।

भारत और नेपाल के मध्य ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक सम्बन्धों की शुरुआत सदियों पहले हो चुकी थी, परन्तु राजनीतिक सम्बन्धों की स्थापना हम १९५० से मान सकते है, जब दोनों देश ३१ जुलाई, १९५० को 'भारत-नेपाल शान्ति और मैत्री सन्धि' पर हस्ताक्षर किये । इस सन्धि के माध्यम से भारत यह चाहता था कि दोनों देशों के मध्य समानता के आधार पर सम्बन्ध स्थापित किये जायें । अतः इस संधि में निम्नलिखित प्रावधान किये गये -

१. दोनों देश किसी विदेशी आक्रमण या उसकी सुरक्षा के लिए उत्पन्न संकट को सहन नहीं करेगा ।
२. अपने प्राचीन सम्बन्धों के आधार पर दोनों देश चिरकालीन शान्ति एवं मैत्री बनाये रखेंगे तथा परस्पर संप्रभुता, अखण्डता एवं स्वतंत्रता को पूर्ण सम्मान देंगे ।
३. सामान्य रुप से नेपाल अपने प्रयोग के लिए युद्ध-सामग्री भारत से खरीदेगा तथा किसी अन्य देश से युद्ध-सामग्री खरीदने से पूर्व वह, भारत से परामर्श करेगा ।
४. तिब्बत, नेपाल और भूटान के मध्य के दर्रों पर निगरानी रखने के लिए भारतीय और नेपाली सेनाए संयुक्त रुप से तैनात की जायेगी ।
५. नेपाली नागरिकों को भारत में नागरिकों का दर्जा दिया जायेगा ।
६. दोनों देशों के नागरिकों को मुक्त आगागमन की सुविधा प्रदान की जायेगी ।

इसी सन्धि के अनुसार दोनों देशों के सम्बन्ध बेहद मैत्रीपूर्ण ढंग से संचालित होते रहे हैं । इसी संधि का लाभ

उठाकर आ लगभग ६ लाख भारतीय नेपाल में रह रहे हैं, जिनमें बिज़नेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर, आई.टी. विशेषज्ञ और श्रमिक सम्मिलित है। इस सन्धि से न केवल भारत को, अपितु नेपाल को अत्यधिक लाभ हो रहा है। भारत में नेपाली लोगों की संख्या लगभग ६ से ८ लाख है। ''दोनों देशों के मध्य गहरे विश्वास व मित्रता को हम दो तथ्यों से परख सकते हैं - पहला नेपाल का दो-तिहाई वैश्विक व्यापार भारत के साथ है तथा दूसरा उसका ९०% आयात-निर्यात भी भारत से ही होता है।''

परन्तु नेपाल को वर्तमान में इस सन्धि पर आपत्ति है और वह लगातार इसे रद्द की मांग भी कर रहा है। नेपाल का मानना है कि चूंकि यह सन्धि १९५० में हुयी थी जब नेपाल में राजतंत्रात्मक शासन था, परन्तु वर्तमान में वह संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष और समाजवादी हो चुका है। इसके अतिरिक्त नेपाल द्वारा भारत के अलावां किसी और देश से युद्ध सामग्री खरीदने से पूर्व भारत से परामर्श करना नेपाली संप्रभुता के विरुद्ध है। इन्हीं आपत्तियों को आधार बनाकर आज नेपाल में भारत विरोधी जनमत का निर्माण किया जा रहा है।

मधेशी समस्या :

नेपाल में पहाड़ी तथा तराई क्षेत्रों के मध्य क्षेत्र को ही मधेशी क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र भारत की सीमा से लगा हुआ है। अत: मधेशी क्षेत्रों की समस्या का प्रभाव भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर पड़ना स्वाभाविक है। चूंकि ये मधेशी मैथिली, भोजपुरी एवं हिन्दी भाषा का प्रयोग करते है, अत: इनके सांस्कृतिक एवं वैवाहिक सम्बन्ध भारतीयों के साथ सदियों से चले आ रहा हैं। यही मधेशी लोग नये संविधान में अपने लिए दो अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, जिसका नाम मिथिलांचल और जनकपुर होगा। किन्तु सितम्बर २०१५ में लागू होने वाले नये संविधान में उनके प्रतिनिधित्व की उपेक्षा की गयी, जिससे उनके नूजातीय संघवाद की मांग पूरी नहीं हो पायी।

चूंकि नेपाल विगत दो दशकों से राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा था। इससे पहले उसे माओवादी हिंसा का सामना करना पड़ा, जिससे तकरीबन २०००० लोगों को जान गवानी पडी। उसके बाद लम्बी राजनैतिक उठा-पठक चली। फिर २०१५ में आये भूकम्प ने वहाँ भारी तबाही मचायी, जिससे सम्पत्ति के साथ मनोवैज्ञानिक नुकसान भी हुआ। नये संविधान के लागू होते ही वहां विरोध प्रदर्शन शुरु हो गये। मधेशी समूहों ने भारत-नेपाल सीमा को बंद कर दिया, जिससे वहां भूकम्प से प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं यथा-दवा, ईंधन, भोजन सामग्री आदि की आपूर्ति बंद हो गयी। इस नाकेबंदी के लिए माओवादियों ने भारत को जिम्मेदार माना। माओवादी पहले से ही मधेशियों को भारत समर्थक मानते आ रहा है। इसलिए माओवादी तथा मधेशियों के बीच कई बार हिंसक संघर्भ भी हो चुका है।

मधेशी आंदोलन भले ही औपचारिक रुप से समाप्त हो गया है, किन्तु उसका दूरगामी परिणाम भारत पर पड़ना स्वाभाविक है। दोनों देशों के मध्य मुक्त आगागमन के प्रावधान के परिणाम स्वरुप भारत में आने वाले नेपाली-प्रवासियों की संख्या में वृद्धि होगी। इसके अलावा मुक्त आवागमन का लाभ उठाकर अनेक आतंकी संगठन भारतीय सीमा में सरलता से प्रवेश कर जाते हैं। सबसे जरुरी बात कि नेपाल का झुकाव लगातार चीन की ओर बढ़ रहा है जो भारतीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है।

सुरक्षा चिंताएं

नेपाल भारत के लिए खुले तौर पर सुरक्षा सम्बन्धी कोई खतरा पैदा नहीं करत सकता है, लेकिन वहां चीन व पाकिस्तान की मौजूदगी भारत की सुरक्षा सम्बन्धी चिंता का कारण जरुर है। भारत में आतंकवादी एवं आपराधिक घटना को अंजाम देने वाला तत्व नेपाल में प्रवेश कर जाते है। नशीली दवाओं का अवैध व्यापार, नकली नोट तथा मानव-दुर्व्यापार भारत-नेपाल सीमा से होते रहे हैं जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नवीन खतरें हैं।

नेपाल में पाकिस्तान खुफियां एजेन्सी आई.एस.आई की संदिग्ध गतिविधियां लगातार बढ़ रही है। आई.एस.आई द्वारा खुफिया ऑपरेशन के लिए नेपाल की सीमा प्रयोग किया जाता रहा है। हाल के वर्षों में भारत भी आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित स्थल माना जा रहा है। इसका कारण है कि यहाँ हथियारों की खरीद-फरोख्य बहुत ही आसानी से हो जाता है। इसके अतिरिक्त नेपाल की चीन से बढ़ती नजदीकी भारत की सुरक्षा चिंता को बढ़ा रहा है। दुर्भाग्यवश नेपाल की माओवादी सरकार भी भारत विरोध के आधार पर ही वहां राष्ट्रवाद का खोखला पोषण करती आ रही है।

नेपाल में चीन की बढ़ती गतिविधि

नेपाल और चीन के बीच राजनयिक सम्बन्ध १९५६ में स्थापित हुए। तब से लेकर अब तक चीन ने नेपाल को अपनी ओर आकर्षित करने का लगभग हर सम्भव प्रयास किया। इसका स्पष्ट प्रमाण है नेपाल की विदेश नीतिम में चीन की ओर स्पष्ट झुकाव। अभी तक नेपाल में भारत से ही निवेश होता आ रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर चीन अब नेपाल में बड़ी परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है। दुर्भाग्यवश नेपाल में २०१५ में आये भूकंप के दौरान मधेशियों द्वारा आर्थिक नाकेबंदी ने चीन को एक अच्छा मौका दे दिया। इस दौरान चीन ने नेपाल को पारगमन के नवीन रास्ते उपलब्ध कराये। इसी दौरान अक्टूबर २०१५ में नेपाल सरकार ने पेट्रोलियम आयात करने के लिए चीन से करार किया। इन सबके के अतिरिक्त ''चीन ने नेपाल सरकार से तिब्बत की राजधानी ल्हासा से काठमांडू तक रेल लाइन बिछाने का समझौता भी कर लिया है।'' नेपाल की सामरिक स्थिति होने के कारण उसे दोनों देशों से ही लाभ उठाने की स्वतंत्रता है। किन्तु नेपाल और चीन के बीच सैनिक सम्बंधो को भी बढ़ावा दिया जा रहा है जो भारत की सुरक्षा के लिए जरुर चिंता का विषय है। दिसम्बर २०१६ में चीन ने नेपाल के साथ अपने पहले संयुक्त सेनाभ्यास की घोषणा की, जिसे नेपाल ने स्वीकार भी कर लिया। यह भारत-नेपाल शान्ति एवं मैत्री सन्धि, १९५० का खुले तौर पर उलंघन था। क्योंकि ऐसा करने से पहले नेपाल को भारत को सूचित या उससे परामर्श करना चाहिए था।

नेपाल का एक घड़ा (माओवादी) भारत को हमेशा से ही एक साम्राज्यवादी देश करते रहे हैं। चीन ने भी सदैव इसी स्थिति का लाभ उठाकर नेपाल में भारत की भूमिका इस तरह पेश किया कि भारत नेपाल के सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा है। इस प्रकार यह मानने में कोई गुरेज नहीं है कि नेपाल द्वारा चीन के साथ सुदृढ़ सम्बन्धों का विकास नेपाल के राष्ट्रीय हितों के मुकाबले भारत को प्रतिसंतुलित करने की भावना से ज्यादा प्रेरित है।

लेकिन पिछले कुछ महीनों से भारत-नेपाल के सम्बंधों में संतुलन स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसकी शुरुआत भारतीय प्रधानमंत्री ने २६ मई, २०१४ की अपनी नेपाल यात्रा से शुरु की थी। नवम्बर, २०१६ में भारतीय राष्ट्रपति के नेपाल यात्रा के दौरान यह बयान आया कि ''भारत नेपाल का संबंध परिवार की तरह है। भौगोलिक और सांस्कृतिक रुप से निकटता ही नहीं, नेपाल-भारत के लोगों में देश की गुंजाइश ही कहा है।''

निष्कर्ष

वैश्विकरण के इस युग में किसी भी देश का विश्व व्यवस्था से अलग रहना उसके राष्ट्रीय के लिए उचित नहीं है और न ही वह देश अन्य देशों के सहयोग के बिना नित नई चुनौतियों का सामना कर सकता है। यही बात नेपाल पर भी लागू होता है। नेपाल को यह भी समझना होगा कि ''चीन उसके ढांचागत संरचना में चाहे जितना निवेश कर ले, किन्तु वह भूगोल की ज्वादतियों को नहीं बदल सकता।'' किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय चीन से कहीं ज्यादा त्वरित सहायता नई दिल्ली ही काठमांडू को पहुँचा सकता है। भारत भी अपने पडोसी देशों के साथ साझेदारी व सहयोग के द्वारा ही अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है।

संदर्भ

1. Bhalla. D. (2016), Strategic Significane of North-East India, IMR Media Pvt.Ltd.
2. http://thediplomat.com/2017/India-and-china-tug-of-war-over-Nepal/
३. पंत, पुष्पेश, (२०१०) भारत की विदेश नीति, नई दिल्ली, टाटा मैक्ग्रा हिल, ऐजुकेशन प्रा.लि.
४. दैनिक जागरण, सितम्बर, १९, २०१६
५. World Focus, Dec. 2017, Page-76,